बुनकरों को सस्ते सूत की सप्लाई

3884. **श्री मोहम्मद अमीन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूत के दामों में 60 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप कपड़े की बिक्री न होने के कारण करघे बंद हो रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने सूत का आयात करके इसे बुनकरों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने का वायदा करने के बावजूद अब तक इस संबंध में कोई समुचित व्यवस्था नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो उनका मंत्रालय उन्हें सूत कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखता है तथा रूई का कितनी मात्रा में आयात किये जाने की संभावना है और उसकी यहां तक पहुंचने की लागत क्या होगी और बुनकरों को यह सूत किन दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न काउंटों के यार्न की कीमतों में 6.2 प्रतिशत से 50.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप हथकरघा क्षेत्र को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ।

(ख) और (ग) सरकार ने सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) स्टैपल रूई का निर्यात बंद कर दिया गया है ।

(2) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत सूती यार्न/सूती फैब्रिक और मेड अप्स के निर्यात के बदले कपास के आयात की अनुमति देने का भी निर्णय किया गया है ।

(3) 60 वाले काउंटों तक के हैंक यार्न का निर्यात बंद कर दिया गया है ।

(4) हथकरघा क्षेत्र को सप्लाई करने की दृष्टि से हैंक यार्न के उत्पादन के लिए कपास की एक लाख गांठों के शुल्क मुक्त आयात का भी निर्णय किया गया है । इस योजना के अंतर्गत कपास की 95000 गांठों के आयात का अनुबंध पहले ही किया जा चुका है। कपास के शुल्क मुक्त आयात से होने वाला कीमत लाभ हथकरघा क्षेत्र तक पहुंचा दिया जाएगा ।

Requirement of cotton

3885. SHRI RAJANI RANJAN SAHU: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that against a requirement of 20 lakh bales of cotton, the present stock is only 15 lakh bales; and

(b) if so, what action Government propose to take to meet the shortfall ?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) According to the most recent estimate of the Cotton Advisory Board, the carry-over stock as on 1-9-1988 will be around 15 lakh bales. Government have already suspended export of staple cotton, permitted import of cotton on Advance Licencing basis against export of cotton yarn, cotton fabrics and made-ups and also permitted import of one lakh bales of medium/long staple cotton duty free during the current